वर्गों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने पर बल देती है।

स्वास्थ्य मूलत: राज्य का विषय है लेकिन सभी ऐसे विवेचित क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करके मदद करता है जो स्वास्थ्य सेवाओं और रोग नियंत्रण को प्रभावित करते हैं। आठवीं योजना में विकास के लिए चुने गए प्रमुख क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित बुनियादी ढांचे का समेकन करना, लोगों को पीड़ित करने वाले प्रमुख संचारी, और गैर-संचारी रोगों का नियंत्रण/उन्मूलन करना स्वास्थ्य जनशक्ति विकास/ जैव-चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी का विस्तार करना शामिल है। जनसंख्या वृद्धि में रोक के साथ साथ शिशु रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्य पर विशेष बल देना ऐसे दोहरे परस्पर जुड़े कार्य हैं जिन पर स्वास्थ्य कार्यनीति की पहलें आधारित हैं।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की पेंशन

*19. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भांति दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को पेंशन देने का विचार रखती है

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अमरीश टाइटलर): (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार, पेंशन देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्पतालों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों के लिए सुविधाएं

*20. **मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ख) इन सुविधाओं को बढ़ाने और उनमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) दिल्ली में के० स० स्वा० यो० के कौन कौन से प्रमुख औषधालय हैं जहां विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य के लाभार्थियों को अस्पताली उपचार सामान्यतया सफदरजंग अस्पताल और डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल में प्रदान किया जाता है। यहां पर सभी प्रमुख विशेषताओं में निदान और उपचार की पूरी-पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली में सेंट स्टीफन्स अस्पताल को निर्धारित दरों के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के उपचार के लिए मान्यता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन के कुछ तथा कई अस्पतालों स्वायत्त और प्राइवेट अस्पतालों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए रेफरल

अस्पतालों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ऐसे अस्पताल प्राय: निदान और हृदय रोग परिचर्या के क्षेत्र में सुपर स्पेसियलिटी सेवाएं प्रदान करते हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की निरंतर समीक्षा की जाती है और लाभार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तथा संसाधनों की उपलब्धता पर सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने और नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास किए जाते हैं। हाल ही में उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय कैमिस्ट की नियुक्ति करना, ताकि औषधों की व्यवस्था के लिए अधिक दुकानें हों, और प्रतिपूर्ति दावों पर कार्रवाई करने में विलम्ब से बचने के लिए इस कार्य का विकेन्द्रीकरण करना भी शामिल है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत प्रत्येक औषधालय को विशेषज्ञ सेवाओं के लिए एक नोडल औषधालय के साथ सम्बद्ध किया गया। इस समय 84 औषधालयों में से 31 औषधालयों में विशेषज्ञ बारी-बारी से उपलब्ध हैं जो शेष औषधालयों को सेवायें प्रदान करते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी लाभार्थियों को विशेषज्ञों की सेवाएं सुलभ हैं।

Forest Area of the Country

1. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what was the forest area of the country during the last five years, yearwise;

(b) whether the expenditure incurred on Van Mahotsaves during above period, yearwise;

(c) whether the expenditure incured on Van Mahotsavas has been commensurate with the results achieved; and

(d) what steps are being contemplated to step up the afforestation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) On the basis of the State of Forest Reports by the Forest Survey of India, forest area of the country recorded during the last five years is as under:—

Year	Forest area in Sq. Km.
1987-88	75,13,46
1988-89	77,00,78
1989-90	77,00,78
1990-91	77,00,78
1991-92	77,00,78

(b) and (c) Van Mahotsav is celebrated by State/Central Govts., Institutions a Voluntary Organisations and others and the expenditure is incidental. The result have been encouraging as these celebrations have been generating mass awareness and enthusiasm amongst the people particularly the younger generation for preservation of environment and love for tree plantation.

(d) a massive programme of afforestation, Social & farm forestry under the 20 Point Programme is pursued vigorously with people's participation. During the Seventh Five Year period 8.8 million hectares were planted up against the target of 8.2 million hectares.

It is proposed to substantially expand the coverage of afforestation/tree planting activities during the Eighth Five Year Plan, which is under finalisation.

Reserved Villages and Forest Villages in Arunachal Pradesh

2. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FARESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the existence if Reserved Villages and Forest Villages in Arunachal Pradesh;

(b) if so, how were these villages established and or who established them, the Government or the people themselves;